भारत भ्रमण पर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

481. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1990 के बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसी अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्या थी और पर्यटन से प्रतिवर्ष प्राप्त आय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई कमी के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री साथ में पर्यटन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री सत्यपाल मलिक): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत स्तर पर सस्ता न्याय दिलाने के लिए कदम

482. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री 22 मार्च, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1201 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि, जैसी कि विधि आयोग ने अपने 114वें प्रतिवेदन में अनुशंसा की थी, पंचायत स्तर पर सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी): ग्राम न्यायालयों की विशेषताओं को, जहां तक संभव हो, पंचायती राजप्रणाली में सम्मिलित करने का विनिश्चय किया गया है।

Number of SC/ST judges and lawyers in the country

483. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) what is the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose names have been recommended for appointment as judges of High Courts State-wise;

(b) what is the number of Scheduled Caste/Schedule Tribe 'District Judges' and 'Additional District Judges' separately in Uttar Pradesh and Delhi; and

(c) what is the number/approximate number of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Advocate/lawyers on the roll of the various district courts and the High Courts of the country at present, State-wise?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) As on date, no recommendation from the Chief Justice and the State authorities in respect of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for appointment as High Court Judges is pending consideration of the Government of India.

(b) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) This information is not maintained.

Comprehensive plan of Punjab Financial Corporation

484. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Punjab Financial Corporation (PFC) has drawn up a comprehensive plan to provide about 75,000 jobs by disbursing loan to the tune of Rs. 458 crores during the Eighth Five Year Plan period; and

(b) if so, what are the broad details of the scheme and its beneficiaries?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) It has been reported by Punjab Financial Corporation (PFC) that they have outlined the